

परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 20 मार्च 2013 पर आधारित है।



परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	—
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	13 मार्च 2013

परियोजना का नाम	पंजाब विकास वित्त कार्यक्रम
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	45288-002
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	—

इस प्रलेख में किसी कंटी कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

क्षेत्र तथा/अथवा उपक्षेत्र वर्गीकरण	सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन/सार्वजनिक व्यय और राजकोषीय प्रबंधन
विषयगत वर्गीकरण	क्षमता विकास आर्थिक विकास अभिशासन
लिंग मुख्यधारा में जोड़ने वाले संवर्ग	कोई लैंगिक तत्व नहीं

■ वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रूपात्मकता	अनुमोदन संख्या	वित्तपोषण का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
तकनीकी सहायता	—	तकनीकी सहायता विशेष निधि	500
ऋण	—	साधारण पूंजी संसाधन	200,000
योग			यूएस \$ 200,500

■ संरक्षा संवर्ग

संरक्षा संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया <http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories> देखें

पर्यावरण	ग
अस्वैच्छिक पुनर्वास	ग
स्वदेशी लोग	ग

■ पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण-पहलू

—

अस्वैच्छिक पुनर्वास

—

स्वदेशी लोग

—

■ स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

—

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

—

■ विवरण

—

■ परियोजना तर्काधार और कंट्री/क्षेत्रीय रणनीति के संबंध में सम्पर्क

प्रस्तावित कार्यक्रम पंजाब में व्यापक राजकोषीय समेकन कार्यक्रम के कार्यान्वयन सरलीकरण का प्रयास है। यह राजकोषीय बचत सृजित करेगा और तद्वारा विकास संवर्धक विकास वित्तपोषण बढ़ाने तथा बनाए रखने में पंजाब की सहायता करेगा। 28 मिलियन जनसंख्या वाला पंजाब मूल रूप से एक कृषि अर्थव्यवस्था राज्य है। पंजाब सन् 1960 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सदैव महत्वपूर्ण रहा है। पंजाब सरकार (जीओपी) राज्य में कृषि के प्रोत्साहन हेतु किसानों को मुफ्त बिजली सहित पारंपरिक रूप से विभिन्न आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। इन स्कीमों के बावजूद, पंजाब में कृषि वर्तमान में उत्पादकता गिरावट, मृदा अवक्रमण तथा जल कमी बाधाओं से ग्रस्त है। पंजाब में स्व-कर तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 8.2 प्रतिशत के अनुपात के साथ अपेक्षाकृत मजबूत स्व-कर प्रयास के बावजूद, पंजाब की अत्यंत नाजुक राजकोषीय स्थिति का कारण तदर्थ व्यय योजना और प्रबंधन के साथ अलक्ष्यकृत अंतरण भुगतान व सब्सिडी स्कीमों को माना जा सकता है। पंजाब में कमजोर होती राजकोषीय स्थिति ने सार्वजनिक संसाधनों को और अधिक दबाव में ला दिया है जिससे विकास वित्तपोषण (निवेश) बाधित होने के फलस्वरूप राज्य में सार्वजनिक सामग्री तथा सेवाओं की प्रदायगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा सब्सिडी मात्र) राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों को चट कर चुके हैं, जिसके कारण राज्य सरकार को इन व्ययों की पूर्ति के लिए और भी अधिक बड़े ऋण लेने की जरूरत पड़ रही है और उससे राज्य बढ़ते चालू खाता (राजस्व) और राजकोषीय घाटे के दुश्चक्र में फंसता जा रहा है। 11वीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान प्रतिबद्ध देयताएं, सब्सिडीज सहित, राजस्व प्राप्तियों की लगभग 100 प्रतिशत थीं। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (पीएसई'ज), जिनमें नव सृजित पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) तथा पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसटीसीएल) शामिल हैं, के कमजोर वित्तीय प्रदर्शन से बढ़ते राजकोषीय असंतुलन और सार्वजनिक ऋण में और वृद्धि हुई है। राज्य की घटिया व्यय योजना और प्रबंधन परंपरा इस राजकोषीय विपत्ति का प्रमुख योगदान रहा है। जीओपी किसी परियोजना के अनुमोदन से पूर्व परियोजना मूल्यांकन की पद्धति का अनुसरण नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन तथा अनुवीक्षण प्रणाली के अभाव से परियोजना के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है, जिसके फलस्वरूप लागतों में वृद्धि होती है तथा परियोजनाएं, बहुधा, इच्छित परिणाम नहीं देती हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, अलक्ष्यकृत बिजली सब्सिडी, लोकप्रिय नीतियों द्वारा प्रेरित, से राज्य के खजाने और बिजली क्षेत्र दोनों को वित्तीय रूप से ढह जाने की कगार पर पहुंचा चुकी है। इसके अनेक निहितार्थ हैं। प्रथम, पीएसपीसीएल बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से कर्ज प्राप्त करने के अवसरों के अभाव में विद्युत अवसंरचना के आधुनिकीकरण में असमर्थ है। द्वितीय, पंजाब सरकार की खराब होती राजकोषीय स्थिति का पंजाब सरकार के विकास एजेन्डा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विशेषकर, अविवेकपूर्ण प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि ने पंजाब सरकार की अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक व्यय के कारगर उपयोग की क्षमता को सीमित करते हुए राजकोषीय विकल्प कम कर दिए हैं। अधिक प्रत्यक्ष रूप से, इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय पर एक बड़ी अवसर लागत राजकोषीय समायोजन के असमानुपाती हिस्से के रूप में पड़ी है।

■ विकास प्रभाव

राज्य में सुधारीकृत और स्थायी विकास वित्तपोषण

■ परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
पंजाब सरकार के बजट में अधिक और स्थायी राजकोषीय गुंजाइश हासिल	—

■ आउटपुट्स और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां और मुद्दे)
1. व्यय दक्षता में सुधार 2. कर और गैर-कर राजस्व प्रयासों में सुधार 3. कुशल ऋण प्रबंधन 4. चुनिंदा पीएसई'ज पुनरगठित।	—

■ व्यवसाय के अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	—
परामर्शी सेवाएं	—
अधिप्राप्ति	—
प्रापण और परामर्शी सूचनाएं	
http://www.adb.org/projects/45288-002/business-opportunities	

■ समयतालिका

अवधारणा मंजूरी	22 नवम्बर 2012
तथ्य-अन्वेषण	22 अप्रैल 2013 से 26 अप्रैल 2013
प्रबंध समीक्षा बैठक	—
अनुमोदन	—
अंतिम समीक्षा मिशन	—

■ संविदाएं और अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	हरण्य मुखोपाध्याय (hmukhopadhyay@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	सार्वजनिक प्रबंधन, वित्तीय सेक्टर और व्यापार प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	वित्त विभाग, पंजाब सरकार

■ सम्पर्क

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/45288-002/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/45288-002/documents
